ACHIEVER IAS ACADEMY

SUMMERY OF THE HINDU

HINDI 28/04/2023



THEHINDU

TALK TO US

- (+918434931877, +917250667974
- 🖂 achieveriaspatna@gmail.com
- www.achieveriaspatna.co.in
- NEW PATLIPUTRA COLONY ROAD
 NO. 4A, NEAR TENNIS COURT,
 PATNA-13



संबंध सीमा पर शांति पर निर्भर राजनाथ चीन से

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को अपने चीनी समकक्ष ली शांगफू से कहा कि मौजूदा समझौतों के उल्लंघन ने द्विपक्षीय संबंधों के पूरे आधार को नष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत-चीन संबंधों का विकास सीमाओं पर शांति और शांति के प्रसार पर आधारित है। लद्दाख गतिरोध के बाद चीन की ओर से यह पहली उच्च स्तरीय सैन्य यात्रा थी। चीनी रक्षा मंत्री शुक्रवार को निर्धारित एससीओ रक्षा मंत्री की बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली में हैं।

कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्रालय भी बेलारूस और ईरान के पर्यवेक्षकों <mark>को भी आमंत्रित किया गया है।</mark> पाकिस्तान वस्तुतः <mark>भाग लेगा।</mark>

ð पुलिस से एक दो दिन पहले आईईडी प्लांट किया गया।

बुधवार को पंतवाड़ा माओवादी हमले की जांच के दौरान, जिसमें 10 सुरक्षा गार्डों सहित 11 लोगों की मौत हो गई थी, जांचकर्ताओं को संदेह है कि घटना से एक या दो दिन पहले आईईडी लगाया गया था। सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ जांचकर्ता ने फेक्सहोल थ्योरी को दोहराया। "सड़क के किनारे खाइयों ने लगभग 60 किलो विस्फोटक लेने के लिए लोहे की सलाखों और छड़ों का उपयोग करके छेद खोदना आसान बना दिया, हमें संदेह है कि यह विस्फोट से एक या दो दिन पहले किया गया था और विस्फोटकों की भारी मात्रा के कारण गहरा गड़ा बन गया"

अधिकारी ने आगे कहा, <mark>"हमें यह भी संदेह है कि उन्हों</mark>ने विस्<mark>फोट के विशिष्ट स</mark>्थान को उठाया क्योंकि यह अरनपुर और सनेली गांव को जोड़<mark>ने वाली सड़क के भीतर का एक क्षेत्र है जहां कुछ प्रकार के फोन सिग्नल उपलब्ध हैं। चार अलग-अलग वाहनों में जंगल <mark>में माओवा</mark>दी विरोधी अभियान से <mark>लौट रहे 50 जवान</mark></mark>

ð केंद्र सरकार। 2 डाक संघों की मान्यता रद्द करता है

किसान विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए केंद्र ने ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयमेंट यूनियन (AIPEU) नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉइज (NFPE) की मान्यता रद्द कर दी है। संचार मंत्रालय ने केंद्रीय सिविल सेवा (सेवा संघों की मान्यता) नियम, 1993 के आधार पर निर्णय लिया। एनएफपीई और एआईपीईयु के खिलाफ एक पार्टी को फंडिंग के आरोप भी लगाए गए थे

ð समान-यौन साझेदारों की चिंताओं को कम करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए सूत्रधार की भूमिका निभाने को तैयार: SC

SC ने गुरुवार को कहा कि वह सरकार को आगे बढ़ाने के लिए एक "सुविधाकर्ता" की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। "बाधाओं" को कम करने के लिए प्रशासनिक कदम उठाने और संयुक्त बैंकिंग, बीमा और स्कूलों में बच्चों के प्रवेश जैसे क्षेत्रों में समान-लिंग भागीदारों के सहवास के दौरान दिन-प्रतिदिन की मानवीय चिंताओं को देखते हुए समान-लिंग की कानूनी मान्यता को खोलना शादी।

याचिकाकर्ता ने समलैंगिक जोड़ों के लिए "पूर्ण विवाह" स्थिति से कम की न्यायिक घोषणा की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा, "हम ऑल या ब्रेक अप्रोच के लिए नहीं जाना चाहते हैं।" अदालत ने "विवाह" के बजाय समान लिंग संघ को लेबल करने के लिए "अनुबंध" या "साझेदारी" का सुझाव दिया।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "शादी के रूप में समान सेक्स संबंधों की कानूनी मान्यता को छोड़कर, अगर वे किसी अन्य मुद्दे का सामना करते हैं, तो उसे संबोधित किया जा सकता है।" 5G ने कहा कि वह इस संबंध में सरकार से परामर्श करेंगे।

सरकार। इस पर स्टैंड यह था कि "शादी" एक विधायिका का विषय है और अदालतों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।



ð नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने तीसरा जहाज आईएनएस तरकश पोर्ट सूडान भेजा।

ऑपरेशन कावेरी के तहत

अब तक की प्रगति

फंसे भारतीयों का 7वां बेड़ा पहुंचा। नयी दिल्ली। भारत ने इसके लिए 3 जहाज INS सुमेधा, INS तेग और INS तारकश तैनात किए हैं।

यात्रियों को पोर्ट सूडान से विभिन्न स्थानों से लाया जाता है, पोर्ट सूडान से उन्हें जे<mark>दा तक पहुँचाया जाता है।</mark> जेदा से उन्हें भारतीय वायु सेना सी-130 जे द्वारा वापस नई दिल्ली लाया गया।

25 अप्रैल को → INS समधा 278 राष्ट्रीय लाए, जिन्हें C-130J की दो सॉर्टियों द्वारा दिल्ली लाया गया।

26 अप्रैल को - INS तेग ने 297 नागरिकों को रवाना किया, जिन्हें C-130J की दो सॉर्टियों द्वारा दिल्ली लाया गया। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि सूडान में अपने नागरिक की मदद के लिए भारतीय "वह सब कुछ करेगा जो करने की आवश्यकता है"।

निकासी में समर्थन के लिए देश सऊदी अरब का ब<mark>हुत आभारी था"।</mark>

उन्होंने आगे कहा कि कई अन्य देशों ने भारत <mark>से अ</mark>पने ना<mark>गरिकों को फेरी लगाने का अनुरोध कि</mark>या है और भारत इस संबंध में सब कुछ करेगा।

वहां की स्थिति "अत्यधिक अस्थिर औ<mark>र अप्रत्याशित"</mark> है। 1700 से 20<mark>00 के बीच भारती</mark>य पहले ही संघर्ष क्षेत्र से बाहर निकल चुके हैं।

ð दिमासा विद्रोही समूह ने केंद्र, असम सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।

असम स्थित एक विद्रोही समूह-दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (डीएनसीए)/दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल (डीपीएससी), जो दीमा हसाओ जिले में संचालित होता है, ने अमित शाह और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में राज्य सरकार और केंद्र के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। अनुबंध के तहत:

- ·डीएमएल<mark>ए के लोग हिंसा छोड़</mark>ने क<mark>ो तैयार हो गए</mark> हैं, अपने संगठन को भंग कर दें। हथियार और गोला-बारूद का समर्पण करें, और मुख्यधारा में शामिल हों।
- असम सरकार राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई पहचान को बनाए रखने, संरक्षित करने, बढ़ावा देने के लिए दिमासा कल्याण परिषद की स्थापना करेगी।
- ·NCHAC और दिमासा पीपुल्स काउंसिल NCHAC नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल के समग्र विकास के लिए 500 करोड़ का पैकेज भी प्रदान किया जाएगा



समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए एचएम अमित शाह ने कहा, "समझौता होगा लेकिन आपातकाल का पूर्ण अंत होगा और आज असम में कोई सशस्त्र समूह नहीं हैं।"

ð जल्द ही भारतीय सेना साइबर ऑपरेशन और विंग्स को समर्थन देगी:-

आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस (एसीसी) में कई प्रमुख फैसले लिए गए। एसीसी ने नेट सेंट्रिक ऑपरेशंस पर वर्तमान फोकस के साथ तत्काल भविष्य में ऑपरेशंस कमांड साइबर ऑपरेशंस एंड सपोर्ट विंग (CCO Sws) का फैसला किया है। साथ ही पांच साल की टेक्निकल एंट्री स्कीम (टीईएस) को चार साल में बदलने का काम किया गया है।

उच्च न्यायालय ने एनआईए से पूछा।

ð बंगाल में रामनवमी के दंगों की जांच के लिए रामनवमी के जुलूसों के दौरान हावड़ा के शिबपुर, उत्तर दिनजबूर के पालखोले और हुगली जिलों में हिंसा भड़क उठी।

ð मोदी ने कांग्रेस द्वारा गारंटी को "फ्रीबी कल्चर" बताया।

पीएम मोदी ने गुरुवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला बोलते हुए कहा, 'शॉर्टकट लेकर देश को इस तरह नहीं चलाया जा सकता. रेवड़ी संस्कृति आने वाली पीढ़ियों के संसाधनों को खा रही है.' कांग्रेस ने गारंटी कार्ड जारी किए हैं जिन पर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डी.के. शिवकुमार ने हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 10 किलो मुफ्त चावल, महिलाओं को 2000 का मासिक प्रत्यक्ष हस्तांतरण का वादा किया है। बेरोजगार युवाओं को 3000 मासिक ट्रांसफर।

खड़गे ने पीएम की तुलना "जहरीले सांप" से की लेकिन बाद में बताया कि उनका मतलब बीजेपी से था

ð भाजपा के साथ कोई समस्या नहीं है। तमिलनाडु प्रमुख: पलानीस्वामी

एआईएडीएमके महासचिव ने एचएम अमित शाह से मिलने के बाद बताया। उन्होंने बताया कि AIADMK और BJP दोनों दलों के बीच गठबंधन जारी रहेगा।"

100वें मन की बात को चिह्नित करने के लिए हास्य पुस्तक।

दुनिया

ð जांच खालिस्तानी उग्रवाद, समीक्षा पैनल ब्रिटेन सरकार से आग्रह करता है।

यूके सरकार द्वारा कमीशन की गई समीक्षा गुरुवार को प्रकाशित हुई थी, इसे बॉस की जॉनसन सरकार द्वारा कमीशन किया गया था। अक्टूबर, 2019 में। इसे एक स्वतंत्र सलाहकार कॉलिन ब्लूम ने लिखा है। सिख अतिवाद पर

- अध्ययन कहता है कि खालिस्तानी चरमपंथी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा, डराने-धमकाने का इस्तेमाल करते हैं। "दिलचस्प बात यह है कि इस क्षेत्रीय दावे में पाकिस्तान में स्थित पंजाब का हिस्सा शामिल नहीं है। यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि प्रेरणा विश्वास आधारित है या नहीं"
- िरिपोर्ट कहती है कि कुछ समूह मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के रूप में उनका प्रतिनिधित्व करके सत्ता और वैधता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। वे हैं। राजनीतिक निकायों की पैरवी करने के लिए "सिख" लेबल। इसमें कहा गया है कि सिख कार्यकर्ता "खतरनाक खतरनाक और आपत्तिजनक इमेजरी" अपलोड करने के लिए फेसबुक और यूट्यूब जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं।
- िरपोर्ट कहती है कि यू.के. सरकार। सिख समुदाय के भीतर उग्रवाद गतिविधि को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और जांच करने की आवश्यकता है। यह आगे कहता है कि सरकार विध्वंसक और सांप्रदायिक गतिविधि की अधिक सूक्ष्म और व्यापक समझ विकसित करेगी

हिंदू राष्ट्रवाद पर

- ब्रिटिश हिंदुओं के "छोटे अल्पसंख्यक" भारत में हिंदू राजनीतिक हित के साथ अपनी पहचान के बारे में अधिक भावुक हो रहे हैं, इसका हवाला दिया गया है - सितंबर 2022 में लीसेस्टर में हिंदू और "मुस्लिम तनाव।
- ·"सरकार <mark>को भी अत्यधिक हिंदू राष्ट्रवाद और बौद्ध राष्ट्र</mark>वाद की बहुत छोटी लेकिन बढ़ती घटना के लिए बहुत अधिक जीवित रहना चाहिए"

ð मानवाधिकारों का हनन: अमेरिकी प्रतिबंध श्रीलंका के पूर्व-नौसेना अधिकारी।

अमेरिका ने LTTE के साथ क्रूर संघर्ष के दौरान मानवाधिकारों के "घोर उल्लंघन" के लिए पूर्व वरिष्ठ श्रीलंकाई नौसेना कमांडर वासंथा करनगोड़ा को मंजूरी दी है:

कोलंबो ने हालांकि कहा है कि "एकतरफा" कदम "काउंटर प्रोडक्टिव" था

श्री करणगोडा वर्तमान में श्रीलंका में एक प्रांत के राज्यपाल हैं। उस पर लिट्टे के साथ 2009 के संघर्ष में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

अमेरिकी विदेश मंत्री ने बयान में कहा, "अमेरिका ने श्रीलंका के नागरिकों के पीड़ितों के लिए सच्चाई और न्याय की तलाश जारी रखी है।"

श्रीलंका में मुख्य तमिल पार्टी तमिल नेशनल एलायंस (टीएनए) ने सरकार की प्रशंसा की है। कदम।



ð ईरान की नौसेना ने ओमान की खाड़ी में तेल टैंकर को जब्त कर लिया

ईरान की नौसेना ने ओमान की खाड़ी में एक मार्शल द्वीप ध्वजांकित तेल टैंकर पर कब्जा कर लिया। टैंकर कुवैत से निकल चुका था और ह्यूस्टन, टैक्सस के लिए निर्धारित था। टैंकरों का नाम एडवांटेज स्वीट है।



ð सूडान ट्रेस पर घड़ी टिकते ही हवाई हमला खार्तूम पर हमला -

सूडानी सेना ने गुरुवार को खार्तूम में अर्धसैनिक बल आरएसएफ पर हवाई हमले किए। गुरुवार को दो गुटों के बीच जानलेवा मारपीट हुई। अमेरिका की मध्यस्थता से तीन दिवसीय युद्धविराम गुरुवार की आधी रात को समाप्त होना था। अमेरिका संघर्षविराम को और 3 दिन और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लड़ाई में अब तक 512 लोग मारे जा चुके हैं और 4,193 घायल हुए हैं।

ð इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में कथित फिलिस्तीनी हमलावर को मार गिराया।

ð शरीफ ने पाक नेशनल असेंबली में विश्वास मत हासिल किया।

सरकार के ब<mark>ढ़ते टकराव के बीच। और शीर्ष न्यायपालिका, विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव</mark> शहबाज शरीफ जीत गए। शाहबाज शरीफ के पक्ष में 342 में से 180 सदस्यों के साथ।

दक्षिण पाकिस्तान में पैसेंजर ट्रेन में बिना किसी कारण के आग लगने से सात की मौत।

ð एक अन्य केन्याई पादरी पर "आदमी द्वारा अपने अनुयायियों की हत्या" का आरोप लगाया गया

ओज़ेकी ओडेरो, न्यू लाइफ प्रेयर सेंटर और चर्च के प्रमुख हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने अनुयायियों की हत्या की:

संपादकीय-1

नासमझ हिंसा

ठेंदक्षिण बस्तर में माओवादियों का हमला समूह की शक्ति का परिचायक है।

ð संपादकीय किस बारे में है?

संपादकीय माओवादी द्वारा हाल ही में किए गए आईईडी विस्फोट के बारे में है जिसमें 10 सुरक्षा कर्मियों और एक नागरिक की मौत हो गई थी। संपादकीय सरकार के कदमों के बारे में कहता है। ऐसे मामलों पर और अंकुश लगाने की जरूरत है।

ð माओवादी हमले के बारे में:

बुधवार को दांते वाडा जिले में माओवादियों द्वारा किए गए एक आईईडी विस्फोट में 10 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई। वे काउंटर माओवादी ऑपरेशन से लौट रहे थे। "जाल सुनियोजित लग रहा था। लेकिन यह सरकार और खुफिया एजेंसियों की विफलता है कि वे पहले ऐसे हमलों की भविष्यवाणी नहीं कर सके।

ð ड्रोन की क्या जरूरत है?

2021 में गृह मंत्री। अमित शाह ने बताया था कि 2010 की तुलना में, जब 10 राज्यों के 96 जिले माओवादी प्रभावित थे, 2021 तक केवल 41 जिले ही माओवादी प्रभावित थे। लेकिन सरकार को यह स्वीकार करना होगा कि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और झारखंड के कुछ जिले अभी भी माओवादी प्रभाव में हैं। जंगलों से भरा कठिन क्षेत्र इन क्षेत्रों को माओवादियों के छिपने का स्थान बनाता है। खराब परिस्थितियों में रहने वाले स्थानीय लोग कई बार माओवादी सरकार का समर्थन करते हैं। स्थानीय जीतने के लिए काम करना चाहिए जो माओवादी सक्रियताओं को स्वचालित रूप से मार डालेगा।

संपादकीय-2

दूसरी पारी की उम्मीद तमिलनाडु में अवैध रेत उत्खनन को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए

ð संपादकीय क्या है

हाल ही में टूथुकुडी तमिलनाडु में एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी (VAO) की सेंड माफिया द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। संपादकीय राज्य में रेत माफियाओं की हत्याओं के बढ़ते मामलों के बारे में बात करता है। यह आगे इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बात करता है।

ð रेत माफिया के अपराधों के बारे में

- • मंगलवार को तमिलनाडु के दूथुकुडी में लोरधू फ्रांसिस वीएओ भीषण रूप से मर्यादा में था।
- पांच साल पहले, पड़ोस के तिरुनेलवेली में, एक 33 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी
- ·25 साल पहले तिरुवल्लूर की जिला कलेक्टर रेत माफिया पर छापा मारने के दौरान लगभग अपनी जान गंवा चुकी थीं।
- अक्टूबर 2013 में: अवैध रेत की पूछताछ गतिविधियों पर मदरसा HC प्रशासन पर भारी पड़ा। राज्य सरकार ने उन्हें तब कलेक्टर को निलंबित कर दिया था।

ð आगे का रास्ता

पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने रेत की बुकिंग और भुगतान की ऑनलाइन प्रणाली के साथ-साथ "एम-सैंड" पर नीतिगत दस्तावेजों का अनावरण करने जैसे कई अभियान शुरू किए हैं। सरकार को नियामक ढांचे को मजबूत करना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण एम-सुंड के अनुसंधान और उत्पादन को बढ़ावा देना भी अपराध को कोई स्थान नहीं देना चाहिए और शिकारियों को न्याय दिलाना चाहिए।

M-sard - (नदी की रेत के विकल्प के रूप में निर्मित रेत।